हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 180 लखनऊ, बुधवार 25 फ़रवरी 2026 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

जेवर एयरपोर्ट पर दो प्रोजेक्ट में 4458 करोड़ निवेश करेगी एआई सैट्स

योगी का सिंगापुर दौरा, दूसरे दिन भी कमाल
एआई सैट्स ने यूपी सरकार के साथ किया एमओयू
जेवर एयरपोर्ट बनेगा नॉर्थ इंडिया का कार्गो हब

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश का एक और तोहफा मिला है। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार

ने एविएशन सर्विस सेक्टर की अग्रणी कंपनी एआई सैट्स के साथ महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत कंपनी गौतमबुद्ध नगर स्थित जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो प्रमुख परियोजनाएं स्थापित करेगी। एक अत्याधुनिक कार्गो कैंपस और दूसरा विश्वस्तरीय एयर कैटरिंग किचेन। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर एआई सैट्स 4458 करोड़ रुपये निवेश करेगी। एमओयू के अनुसार एआई सैट्स जेवर एयरपोर्ट परिसर में अत्याधुनिक कार्गो कैंपस का निर्माण करेगी। यह कार्गो कैंपस न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एयर फ्रेट और लॉजिस्टिक्स का प्रमुख केंद्र बनेगा। इस परियोजना से निर्यात–आयात गतिविधियों को गति मिलेगी, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्रों को बड़ा लाभ होगा। एमओयू के दूसरे प्रमुख निवेश के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही एक अत्याधुनिक विश्वस्तरीय एयर कैटरिंग किचेन की स्थापना की जाएगी। यह किचेन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होने वाली उड़ानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री के सिंगापुर दौरे का उद्देश्य वैश्विक निवेशकों को उत्तर प्रदेश की संभावनाओं से जोड़ना है। दूसरे दिन हुए इस एमओयू को राज्य के एविएशन, लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट के चालू होने के साथ ही यह कार्गो कैंपस और एयर कैटरिंग सुविधा उत्तर भारत के आर्थिक परिदृश्य को नई दिशा देंगे और प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर और मजबूत स्थिति में स्थापित करेंगे।

इन्वेस्ट यूपी व एससीई के बीच एमओयू
सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइज के साथ करार

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी इन्वेस्ट यूपी और सिंगापुर सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइज एससीई के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू के तहत दोनों पक्ष विषयगत ज्ञान के आदान–प्रदान, तकनीकी सहयोग और परामर्श सेवाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सतत आर्थिक विकास, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आधुनिक अवसंरचना के विकास को गति देने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। दोनों पक्ष न सिर्फ स्टडी विजिट्स व लीडरशिप डेलिगेशन का आयोजन करेंगे, बल्कि ट्रेनिंग व कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों का खाका तैयार कर उसे लागू भी कराएंगे। दो माह के भीतर विस्तृत परियोजना समझौतों पर बातचीत शुरू की जाएगी और छह माह के भीतर उन्हें अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाएगा। इस साझेदारी से उत्तर प्रदेश को सिंगापुर के प्रशासनिक अनुभव, शहरी नियोजन, औद्योगिक क्लस्टर विकास, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में अनुभव का लाभ मिलेगा।

पढ़ाई के दबाव की वजह से बेटे ने की बाप की हत्या, आरी से काटा शव, नीले ड्रम में धड़ रख भरा सीमेंट

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। आशियाना के सेक्टर एल में रहने वाले शराब कारोबारी व पैथालॉजी संचालक मानवेंद्र सिंह (49) की उन्हीं के बेटे अक्षत प्रताप सिंह (21) ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद शव के टुकड़े कर दोनों हाथ व पैर पारा के सदरौना इलाके में फेंक दिए। सिर सहित धड़ घर के भीतर ड्रम से बरामद किया गया है। पुलिस ने बेटे के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी मध्य विक्रांत वीर के मुताबिक 21 फरवरी को आशियाना थाने पर मानवेंद्र सिंह की गुमशुदगी की शिकायत मिली थी। पुलिस ने सचिवालय सुरक्षा में तैनात मानवेंद्र के भाई अरविंद कुमार से मामले की जानकारी ली। इसके बाद अक्षत से पूछताछ की तो पता चला कि मानवेंद्र बेटे पर नीट परीक्षा की तैयारी का दबाव बना रहे थे। 20 फरवरी को सुबह 4रू30 बजे इसी बात को लेकर पिता–पुत्र में विवाद हो गया। गुस्से में आकर अक्षत ने पिता को लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी। मानवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के वक्त अक्षत की छोटी बहन कृति अपने कमरे में सो रही थी। आवाज सुनकर वह कमरे में पहुंची तो पिता का शव कमरे में पड़ा था। मानवेंद्र के पिता सुरेंद्र पाल सिंह सेवानिवृत्त दरोगा हैं। वह जालौन में रहते हैं। घटना सूचना पर आशियाना पहुंच गए हैं। पुलिस ने शव के टुकड़ों को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया है। हाथ और पैर बरामद कर लिए गए हैं। वारदात मकान के तीसरे तल पर हुई। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद वह शव को घसीटते हुए भूतल पर लाया। यहां खाली कमरे में शव रख दिया। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। पहले कार में लादकर गोमती नदी में फेंकने की साजिश रची, लेकिन शव का वजन ज्यादा था। इससे वह अकेले ऐसा नहीं कर पाया। इसके बाद आरी खरीदकर लाया और पिता के शव के टुकड़े कर दिए। धड़ ठिकाने नहीं लगा सकने पर नीला ड्रम खरीदकर लाया और उसमें डाल दिया। इससे पहले कि अक्षत धड़ को ठिकाने लगाता उसकी करतूत उजागर हो गई। पड़ोसियों को छानबीन करता देख अक्षत घबरा गया। उसे आभास हुआ कि पड़ोसियों को उस पर शक हो गया है।

इसके बाद सोमवार दोपहर दो बजे उसने पिता के करीबी दोस्त सोनू को फोन किया। अक्षत ने उनसे कहा कि अंकल, पापा ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर सोनू भागकर मानवेंद्र के घर पहुंचे। परिजनों के मुताबिक सोनू ने अक्षत से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि 20 फरवरी को पापा ने सुसाइड कर लिया था। सोनू ने देर से जानकारी देने पर उसे डांट लगाई। फटकार के बाद कड़ाई से पूछताछ की तो अक्षत टूट गया और पूरी कहानी बताई। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। खास बात यह है कि मानवेंद्र के भाई अरविंद उसी मकान में दूसरे तल पर परिवार के साथ रहते हैं। वारदात के वक्त भी वह दूसरे तल पर थे। हालांकि, सुबह होते ही परिवार के साथ जालौन चले गए। डीसीपी का कहना है कि कई बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। छानबीन में सामने आया है कि चार माह पहले मानवेंद्र के मकान से कीमती गहने चोरी हो गए थे। उन्होंने कामवाली पर शक जताते हुए थाने में शिकायत की थी। हालांकि, बाद में उन्हें पता चला कि जेवर कामवाली ने नहीं चोरी किए हैं। बेटे की करतूत छिपाने के लिए उन्होंने थाने से शिकायत वापस ले ली थी। इसके बाद से वह बेटे की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। 22 फरवरी को तड़के उन्होंने अक्षत को पढ़ाई के लिए समझाया था, जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दे दिया। परिजनों ने बताया कि अक्षत ने एक कोचिंग से नीट की तैयारी की थी। वह दो बार परीक्षा भी दे चुका था, पर सफल नहीं हो पाया था। मानवेंद्र की चार पैथालॉजी और तीन शराब की दुकानें हैं। अक्षत ने लामार्ट से 12वीं की पढ़ाई की है।

सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से मिले योगी

एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए निवेश का दिया आमंत्रण

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के उपप्रधानमंत्री एवं व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम योंग तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के समन्वय मंत्री और गृह मंत्री के. शनमुगम से मुलाकात की। चर्चा का केंद्र उत्तर प्रदेश में शहरी नियोजन, आंतरिक सुरक्षा ढांचे और डिजिटल गवर्नेंस में सिंगापुर की विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश

को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रहा।गान किम योंग के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के श्प्रो–बिजनेसश वातावरण पर जोर दिया। उन्होंने राज्य के विशाल लैंड बैंक और शीघ्र ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर से मिलने वाली कनेक्टिविटी को रेखांकित किया। बैठक में दिल्ली एनसीआर में सिंगापुर की कंपनियों द्वारा औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई, जिसमें सेमीकंडक्टर निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन मॉड्यूल पर विशेष फोकस रहा।के. शनमुगम के साथ संवाद में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बेहतर होती कानून–व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर चर्चा की, जिसमें सिंगापुर के तकनीक–एकीकृत पुलिसिंग मॉडल और आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान दिया गया। सिंगापुर के कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने स्वतंत्र वित्तीय कोषों और निजी निवेशकों को राज्य के लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। नियामक प्रक्रियाओं के सरलीकरण और सिंगल–विंडो क्लीयरेंस प्रणाली से उत्तर प्रदेश में बड़े प्रोजेक्ट्स के पूरे होने की समय–सीमा में उल्लेखनीय कमी आई है।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2026–27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं

बीएनई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026–27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट संकल्प (एसएएनकेएएलपी) विषयवस्तु पर आधारित है, जिसमें समावेशी विकास एवं अवसंरचना को तेज करना और निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। वर्ष 2023 में सत्ता में आई भाजपा के नेतृत्व वाली विष्णु देव साय सरकार का यह तीसरा बजट है। सरकार का पहला बजट ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) विषयवस्तु पर आधारित था, जबकि पिछले साल यह गति (सुशासन, अवसंरचना को तेज करना, प्रौद्योगिकी और आद्योगिक विकास) पर केंद्रित था। राज्य सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत भूमिहीन श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जो किसानों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह आंकड़ा राज्य की कृषि उत्पादन क्षमता और समर्थन मूल्य नीति की सफलता को भी दर्शाता है। सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए निशुल्क पंप योजना हेतु 5500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जयशंकर और जीसीसी के महासचिव की मुलाकात, FTA पर बातचीत; व्यापार और ऊर्जा सहयोग को मिलेगा नया बल

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) के महासचिव जसीम मोहम्मद अलबुदैयी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस बात की जानकारी जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं। इस बैठक के

दौरान भारत और जीसीसी के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर आधिकारिक रूप से बातचीत शुरू करने के लिए एक संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए गए। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और जीसीसी संयुक्त कार्ययोजना हमारे रणनीतिक संवाद के तहत व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कृषि, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रस्तावित एफटीए दोनों पक्षों की साझेदारी को नई ऊंचाई देगा।

भारत के लिए जीसीसी अहम, कैसे?

बता दें कि भारत के लिए जीसीसी देश बेहद अहम हैं। साल 2024–25 में भारत और जीसीसी के बीच कुल व्यापार लगभग 178.56 अरब डॉलर रहा, जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का करीब 15.42 प्रतिशत है। पिछले पांच वर्षों में भारत और जीसीसी के बीच व्यापार लगातार बढ़ा है। इस दौरान औसतन 15.3 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर्ज की गई है।

दोनों पक्षों के बीच FTA से क्या होगा?

दूसरी ओर विशेषज्ञों का मानना है कि मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) लागू होने से तेल और गैस जैसे ऊर्जा क्षेत्रों के साथ–साथ निवेश, कृषि और अन्य क्षेत्रों में भी व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। इससे भारत और खाड़ी देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे।

स्थिति स्पष्ट होते ही अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता शुरू करेगा भारत, केंद्रीय मंत्री का बयान

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि जैसे ही अमेरिका में टैरिफ को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी, भारत व्यापार वार्ता फिर से शुरू करेगा। उन्होंने यह बात तब कही, जब उनसे पूछा गया कि भारत कब अमेरिका के साथ दोबारा व्यापार वार्ता शुरू करेगा। भारत और अमेरिका ने 22 फरवरी को तय किया था कि उनके मुख्य वार्ताकारों फिर बैठक करेंगे, जो इस सप्ताह वॉशिंगटन में प्रस्तावित थी। बैठक इसलिए होनी थी कि अंतरिम व्यापार समझौते का अंतिम मसौदा तैयार किया जा सके। भारतीय टीम 23 फरवरी से अमेरिका में तीन दिवसीय बैठक शुरू करने वाली थी। जब उनसे पूछा गया कि भारत में चीनी निवेश को बढ़ाने के लिए प्रेस नोट 3 के तहत लगे प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी, तो गोयल ने कहा कि मंत्रालय उद्योग के साथ संवाद में है, ताकि मुद्दों को समझा जा सके और पड़ोसी देशों के साथ निवेश को आसान बनाया जा सके, जहां संबंध बेहतर हुए हैं। इस प्रेस नोट के तहत, भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए सरकार की अनिवार्य मंजूरी चाहिए। इन देशों में चीन भी शामिल है। गोयल ने कहा, यह प्रेस नोट 3 भारतीय उद्योग और व्यवसायों को अवसरवादी अधिग्रहण से सुरक्षित रखने के लिए लाया गया था। खासकर महामारी के समय, जब कंपनियों का मूल्यांकन बड़ी बात माना जाता है। हमारी सरकार बदलती परिस्थितियों और समय के अनुसार विचारों को सुनने वाली सरकार है। हम हमेशा नए विचारों के लिए खुले हैं और समय के साथ बदलाव के लिए तैयार भी हैं। उन्होंने कहा, हम खुले दिमाग से देख रहे हैं कि चीन से बेहतर तकनीक और अधिक निवेश कैसे लाया जा सकता है। हम संवाद में हैं और देखेंगे। गोयल ने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार को घरेलू उद्योगों से परामर्श कर यह देखना होगा कि वास्तव में क्या करना जरूरी है। यह संतुलित कदम हो सकता है। यह चरण–दर–चरण हो सकता है।

'केरलम' के नाम से जाना जाएगा केरल! मोदी कैबिनेट ने दी नाम बदलने की मंजूरी

एजेंसी

नयी दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने राज्य 'केरल' का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय राज्य सरकार के अनुरोध

और विधानसभा के प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। सरकार के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति अब केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को केरल की राज्य विधानसभा के पास उसकी राय जानने के लिए भेजेंगे। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत पूरी की जाएगी। राज्य विधानसभा से प्राप्त सुझावों और विचारों के बाद भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। इसके पश्चात राष्ट्रपति की सिफारिश लेकर केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को संसद में पेश किया जाएगा।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, श्जब से भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ, तब से इसकी मांग थी कि केरल का नाम केरलम होना चाहिए। इस मांग को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह कदम राज्य में इस साल होने वाले केरल विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है।दरअसल, केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को एक प्रस्ताव पारित कर राज्य का नाम 'केरल' से बदलकर 'केरलम' करने की सिफारिश की थी। इसके बाद केरल सरकार ने भारत सरकार से संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर नाम परिवर्तन करने का औपचारिक अनुरोध किया था। यदि संसद इस विधेयक को पारित कर देती है, तो आधिकारिक रूप से राज्य का नाम 'केरलम' हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को श्रीनगर हवाई अड्डे पर 1,677 करोड़ रुपये की लागत से सिविल एन्क्लेव बनाने को मंजूरी दे दी है।

राहुल की मोहब्बत की दुकान में मिलता है 'नफरत और भारत विरोध' का सामान : ब्रजेश

बब्बर शेर' नही 'विदेशी शक्तियों के प्यादे' बनकर रह गये राहुल गांधी

संवाददाता

लखनऊ। भाजपा नेता व प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गाँधी की तथाकथित मोहब्बत की दुकान में केवल और केवल 'नफरत, अराजकता, दंगा और भारत विरोध' का सामान मिल रहा है। बीजेपी के सूबाई दफ्तर में मीडिया से मुखातिब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने झूठ की राजनीति के उस स्तर को छू लिया है, जहाँ से वापसी संभव नहीं है। जिस प्रकार के अनर्गल और तथ्यहीन आरोप राहुल गांधी हर दिन प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार पर लगाते हैं और सोशल मीडिया पर विष–वमन करते हैं, वह न केवल निंदनीय हैं बल्कि 'राष्ट्रद्रोह' की श्रेणी में आता है। आज देश देख रहा है कि राहुल गांधी की राजनीति का स्तर किस कदर गिर चुका है। उनका एकमात्र उद्देश्य अब झूठ पर झूठ बोलना, जनता को उकसाना, अराजकता फैलाना और भारत की ताकत को नीचा दिखाना रह गया है। जब भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, तब एआई ग्लोबल समिट में कांग्रेस नेताओं ने नंगा नाच कर न केवल देश की गरिमा को तार–तार किया बल्कि देश को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रची। आज राहुल गाँधी ने इस 'नंगा नाच' का समर्थन कर इन नंगे कांग्रेसियों को बब्बर शेर कहा है। राहुल गांधी द्वारा इस कृत्य का समर्थन करना यह सिद्ध करता है कि इस पूरी पटकथा के सूत्रधार वही हैं। विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है लेकिन विरोध के नाम पर 'नग्नता' और 'अराजकता' का सहारा लेना भारतीय संस्कृति और भारत की महान विरासत के खिलाफ है। राहुल का मतलब रा–रार, हु – हुड़दंग, ल– लफंगई। देश की जनता अराजकता फैलाने वाली इस नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। विदेशी प्रोपेगेंडा मशीनों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछालना राहुल गाँधी की पुरानी आदत है। लेकिन याद रखिए,

सूरज पर थूकने से खुद का चेहरा ही गंदा होता है। देश की जनता अराजकता फैलाने वाली नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। राहुल गाँधी खुद को 'बब्बर शेर' होने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप केवल 'विदेशी शक्तियों के प्यादे' बनकर रह गए हैं। राहुल गांधी का एजेंडा स्पष्ट है–भारत की बढ़ती इकोनॉमी को रोकना और दुनिया भर में भारत की छवि को धूमिल करना। राहुल गांधी देश में भारत विरोधी ताकतों के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए हैं। राहुल गांधी देश में नकारात्मक राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। देश में अराजकता फैलाना, दंगे कराना, विदेशी मंचों पर भारत को बदनाम करना, फेक न्यूज फैलाकर लोगों को उकसाना, अफवाह फैला कर आंदोलन कराना ही राहुल गांधी की राजनीति का परिचय है। राहुल गांधी गालियां देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। कल जिस तरह से राहुल गांधी ने फिर अनर्गल प्रलाप किया है, झूठ का प्रपंच किया है, उससे स्पष्ट है कि राहुल गांधी अब अराजकता पर उतर आए हैं। देश को हर दिन बदनाम करना और मोदी को गाली देना राहुल गांधी का पैशन और फैशन, दोनों बन चुका है। सच्चाई यह है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से फंड लेने वाले लोग आज हमें 'देश रक्षा' का पाठ पढ़ा रहे हैं। जनता सब देख रही है और कांग्रेस तथा राहुल गांधी के 'झूठ के साम्राज्य' को बहुत जल्द जमींदोज कर देगी।

संपादकीय

निजी अस्पताल, यानी जेबें खाली करने के संस्थान

कुछ साल पहले गुडगांव से एक लड़की ने लिखा था कि अपने पति को बुखार के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां रात भर उसके पति के तरह–तरह के टैस्ट चलते रहे। दो दिन बाद छुट्टी के वक्त 10 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया गया। एक दूसरे लड़के ने अपनी मां के बारे में एक दुखद घटना लिखी थी। उसने बताया कि मां को पेट में दर्द हुआ। अस्पताल में बताया गया कि मां के गाल ब्लैडर में पथरी है। उनका इलाज होता रहा लेकिन तबियत बिगड़ती गई। उसने मां को कहीं और ले जाने की बात की, लेकिन डराया गया कि कहीं रास्ते में ही कुछ न हो जाए। कहा गया कि तबियत जैसे ही सुधरेगी, पथरी का आप्रेशन किया जाएगा। लेकिन तबियत नहीं सुधरी, और अंत में मां की मृत्यु हो गई। तब लड़का मां के पोस्टमार्टम पर अड़ गया। पोस्टमार्टम में जो दिल दहला देने वाली बात सामने आई, वह यह थी कि उसकी मां को पथरी थी ही नहीं। बहुत से निजी अस्पतालों में जब से मार्कीटिंग नामक विभाग का प्रवेश हुआ है, तब से डाक्टरों को टारगेट्स दिए जाने लगे हैं। टारगेट का मतलब ही यही है कि उन्हें कितना पैसा कमाकर अस्पताल को देना है। ऐसे में डाक्टर अधिक से अधिक दवाएं लिखते हैं, जिन टैस्टों की जरूरत नहीं होती, वे भी कराए जाते हैं। हाल ही में संसदीय कमेटी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में 40 प्रतिशत से अधिक ऐसे आप्रेशन किए जाते हैं, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती। भारत में लोग डाक्टरों को देवता के रूप में देखते हैं। जो उन्होंने कह दिया, वही ठीक है। आम आदमी को मालूम ही नहीं होता कि जिस मरीज को वह अस्पताल में ठीक कराने के लिए लाया है, वह अस्पताल के लिए मुनाफा कमाने की मशीन है। इसके अलावा जिन लोगों के पास मैडिक्लेम होता है, उसके अनुसार जितनी राशि मरीज को दी जा सकती है, जब तक उसे पूरी तरह न वसूल लिया जाए, मरीज को नहीं छोड़ा जाता। मैडिक्लेम कम्पनियां इस बारे में सरकार से शिकायत भी कर चुकी हैं। हाल ही में राज्यसभा की सदस्य स्वाति मालीवाल ने इस मसले को उठाया था। उन्होंने कहा कि बहुत से अस्पतालों के बैड के चार्जेज फाइव स्टार होटलों से भी ज्यादा हैं। मरीज से पूछा जाता है कि क्या उसके पास स्वास्थ्य बीमा यानी कि मैडिक्लेम है और हां कहते ही फौरन बिल का मीटर चालू हो जाता है। मरीजों को वे दवाएं भी दे दी जाती हैं, जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती। इसके अलावा बहुत सी वे दवाएं होती हैं जो सिर्फ अस्पतालों की दुकानों या किसी विशेष दुकान पर ही मिलती हैं। जो मरीज 5 दिन में ठीक हो सकते हैं, उन्हें 10–15 दिन अस्पताल में रखा जाता है। स्वाति ने जो सवाल उठाए हैं, वे अर्से से महसूस किए जा रहे हैं लेकिन मजाल है कि तमाम मामलों पर हर रोज आंदोलन करने वाले इन बातों पर कभी बोलते हों। यह भी है कि मरीज की मृत्यु के बाद भी, उसे वहां कई–कई दिन तक रखा जाता है। मृत्यु के बाद आप्रेशन का बहाना बनाकर आप्रेशन की मोटी फीस ली जाती है, फिर कह दिया जाता है कि आप्रेशन के दौरान मरीज की मृत्यु हो गई। पहले सोचते थे कि सरकारी अस्पतालों की जगह निजी अस्पतालों में इलाज ठीक होता है, मगर अब सोच उलटी हो गई है। लोग कहने लगे हैं कि सरकारी अस्पतालों में भीड़ बहुत होती है लेकिन वहां डाक्टरों के ऊपर टारगेट पूरा करने और नौकरी बचाने का कोई दबाव नहीं होता, इसलिए वे इलाज ठीक करते हैं। अपने इस इतने बड़े देश में कोई सरकार चाहे तो हर जिले में ऐसे सुविधाजनक अस्पताल खोल सकती है, जहां मरीज को ठीक–ठाक इलाज मिले। उसकी देखभाल करने वालों को भी कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएं। क्योंकि मरीज के मुकाबले उसकी देखभाल करने वालों की मामूली सुविधाओं का ध्यान कहीं नहीं रखा जाता। यदि सरकारों को लगता है कि उनके पास इतनी राशि नहीं है, तो क्यों न ऐसा करके देखा जाए कि किसी जिले में अस्पताल बनवाने के लिए वहां रहने वाले हर व्यक्ति से 10 रुपए मांगे जाएं। उन्हें पूरी योजना की जानकारी दी जाए। सरकार इसके लिए जिला अधिकारी की निगरानी में एक अकाऊंट खोले। यकीन मानिए कि लोग बड़ी संख्या में आगे आएंगे। ऐसे धनाढ्य लोग जो 10 के मुकाबले लाखों भी दे सकते हैं, वे भी इसमें भागीदारी करेंगे। करके तो देखिए। लेकिन करे कौन और क्यों करे? जब तरह–तरह के फालतू और आग लगाऊ बयानों से ही दलों का काम चल जाता है, तो वे ऐसे काम क्यों करें, जहां वाकई कोई कठिन प्रयत्न करना हो। सोचा तो यह गया था कि प्राइवेट अस्पताल आएंगे, तो लोगों को अच्छा इलाज मिलेगा। उन्हें दर–दर भटकना नहीं पड़ेगा लेकिन हो यह रहा है कि एक इलाज कराने में ही मध्यवर्ग के लोगों की सारी बचत खत्म हो जाती है। खाता खाली हो जाता है। मैडीकल माफिया की दादागिरी भी झेलनी पड़ती है। गरीब की तो कौन कहे। साधारण आदमी जाए, तो जाए कहां। वोटर को भगवान मानने वाले लोगों तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती।

राशिफल

मेष :– जीविका क्षेत्र में अवरोधों से मन में निराशा संभव। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यय अपेक्षित है। नई सफलताओं से खुद की क्षमताओं का एहसास होगा। संतान संबंधी दायित्वों की पूर्ति होगी।

बृषभ :– शासन–सत्ता से जुड़े लोगों के साथ निकटता बढ़ेगी। नियोजित परिश्रम द्वारा कार्य पूर्ण होने के आसार बनेंगे। पुराने संबंधों से लाभ होगा। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा।

मिथुन :– संबंधों में व्यवहार कुशल बने। सामाजिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों में आपकी भागेदारी संभव। निकट संबंधों में अपनी अच्छी छबि बनायें। कुछ महत्वपूर्ण प्रयत्न की सार्थकता से उत्साहित होंगे।

कर्क :– विद्यार्थियों के लिए ग्रहों की अनुकूलता लाभप्रद होगी। कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं सार्थक होंगी। नवीन आशाएं नये उत्साह का संचार करेंगी। कार्यक्षेत्र में संबंधों का भरपूर लाभ उठाएंगे।

सिंह :– अंतमरुखी स्वभाव को त्याग बाह्यमुखी बनायें। कुछ महत्वपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति होने के आसार हैं। सामान्य दिनर्चया के साथ बीत रहे जीवन में उत्साह का अभाव रहेगा। घर में खुशहाली रहेगी।

कन्या :– पुरानी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सुख की अनुभूति करेंगे। ग्रहों की अनुकूलता से अवरोधित कार्य हल होंगे। शिक्षा में समुचित परिश्रम करने में असमर्थ मन नकारात्मक चिंताओं से बोझिल होगा।

तुला:– किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव। पारिवारिक वातावरण में उत्साह का माहौल रहेगा। दुबिधाओं का त्याग कर लक्ष्य पर केंद्रित हों।

वृश्चिक :– कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मन पर प्रभावी होंगी। घरेलू कायरें में ब्यस्तता बढ़ेगी। परिजनों के भावनात्मक सहयोग से मन उत्साहित होगा। हंसमुख स्वभाव से आसपास का माहौल प्रसन्न होगा।

धनु :– कठिन एवं विषम स्थितियों के मध्य परिश्रम व लगन से प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। सामाजिक सक्रियता से मान–प्रतिष्ठा में बढ़ेगी। घरेलू दायित्वों की पूर्ति होगी। जीवन साथी के साथ मधुरता कायम रखें।

मकर :– कुछ भौतिक आकांक्षाएं अपनी सार्थकता हेतु मन को उद्वेलित करेंगी। निकट संबंधों में भावनात्मक अपेक्षाएं कष्टकारी हो सकती हैं। गैर सांस्कारिक कायरे की आकर्षित मन पर अंकुश लगायें।

कुंभ :– कुछ नई इच्छाएं बलवती होंगी। प्रयासरत् क्षेत्रों में संघर्ष संभव परंतु निराशावादी विचारों को मन में स्थान न दें। किसी बड़े आयोजन हेतु समुचित ऊर्जा की अनुभूति होगी। रोजगार में लाभकारी स्थिति रहेगी।

मीन :– नकारात्मक चिंताओ को त्याग अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। नौकरी–पेशे में अधिकारियो व सहकर्मियो के सहयोग से वातावरण सुखद होगा। राजनीति से जुड़े लोगों का सहयोग मिलेगा।

क्लिक के दलदल में फँसा समाज : गालियों से ग्रोथ, शोर से शोहरत

—डॉ. सत्यवान सौरभ

डिजिटल दुनिया कभी ज्ञान, संवाद और रचनात्मकता की प्रयोगशाला मानी जाती थी। यह विश्वास था कि इंटरनेट लोकतंत्र को मज़बूत करेगा, हाशिये पर खड़े लोगों को आवाज़ देगा और असली प्रतिभा को पहचान दिलाएगा। लेकिन आज जब हम स्क्रीन पर उँगली चलाते हैं, तो एक अलग ही सच सामने आता है। यहाँ हुनर से ज़्यादा हंगामा बिकता है, विचार से ज़्यादा विवाद और मेहनत से ज़्यादा मीम। थ्बमइववा और प्देजंहतंउ जैसे मंचों पर 'वायरल' होना सफलता की कसौटी बन चुका है। सवाल यह नहीं कि लोग मशहूर क्यों हो रहे हैं, सवाल यह है कि हम किस तरह की मशहूरी को पुरस्कार बना रहे हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का पूरा ढांचा ध्यान के व्यापार पर टिका है। जितनी देर आप स्क्रीन पर टिके रहेंगे, उतना अधिक मुनाफ़ा पैदा होगा। इस गणित में शोर सबसे सस्ता और असरदार हथियार है। ऊँची आवाज़, उग्र भाषा, भड़काऊ हावभाव और अति–नाटकीयता कृ यही वह मुद्रा है जिसे एल्गोरिद्म सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जो व्यक्ति ठहराव से, तर्क से और संयम से बात करता है, वह भीड़ में गुम हो जाता है, जबकि तमाशा करने वाला मंच के बीचोंबीच बैठा होता है। यह केवल कंटेंट की समस्या नहीं है, बल्कि प्रोत्साहन की है। जब प्लेटफ़ॉर्म वही दिखाते हैं जो क्लिक दिलाता है, तो रचनाकार भी वही बनाने को मजबूर होता है। इस दौड़ में गुणवत्ता पीछे छूट जाती है और उत्तेजना आगे बढ़ती जाती है। धीरे–धीरे यह एक आदत बन जाती है, और आदत अंततः संस्कृति में बदल जाती है। कभी हुनर का अर्थ था कृ अभ्यास, अनुशासन और धैर्य। आज हुनर का मतलब है ट्रेंड पकड़ लेना। कोई सड़क पर नाचकर मशहूर है, कोई गालियाँ देकर 'बोल्ड' कहलाता है, कोई निजी जीवन को सार्वजनिक तमाशा बनाकर 'रियल' होने का दावा करता है। असली प्रश्न यह नहीं कि ये लोग क्यों देखे जा रहे हैं, बल्कि यह है कि समाज किस तरह के आदर्श गढ़ रहा है। यह नया मापदंड युवाओं के मन में एक खतरनाक संदेश बैठा रहा है कृ कि शॉर्टकट ही सफलता है। अगर आप शांत हैं, तो आप उबाऊ हैं। अगर आप गहरे हैं, तो आप अप्रासंगिक हैं। यह सोच न केवल कला और ज्ञान का अपमान है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ज़हरीली है। युवा खुद को लगातार तुलना के आईने में देखने को मजबूर है, जहाँ आत्मसम्मान लाइक्स और व्यूज़ की संख्या से तय होता है। डर इस बात का है कि आने वाली पीढ़ी किताबें ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि कंटेंट के लिए पढ़े। इतिहास, साहित्य और दर्शन अब सीखने के साधन नहीं, बल्कि विवाद पैदा करने की सामग्री बनते जा रहे हैं। लंबी सोच, संदर्भ और नैतिकता कृ इन सबको 'बोरिंग' कहकर किनारे किया जा रहा है। जबकि सच यह है कि ज्ञान कभी त्वरित नहीं होता। वह समय मांगता है, धैर्य मांगता है और असहज सवालों से जूझने की ताक़त मांगता है। आज सच बोलने वाले के पास अक्सर सन्नाटा होता है। उसकी बातों में सनसनी नहीं होती, उसके निष्कर्ष तुरंत तालियाँ नहीं बटोरते। दूसरी ओर, तमाशा करने वालों के पास मेला होता है कृ लाइक्स, शेयर, फ़ॉलोअर्स और ब्रांड डील्स। यह असंतुलन खतरनाक है, क्योंकि समाज शोर से नहीं, संवाद से आगे बढ़ता है। जब संवाद की जगह शोर ले लेता है, तो बहस तमाशा बन जाती है और असहमति दुश्मनी। युवावर्ग इस पूरे परिदृश्य में सबसे ज़्यादा उलझन में है। एक ओर रोज़गार की अनिश्चितता, दूसरी ओर डिजिटल चमक का झूठा वादा। उसे बताया जा रहा है कि पहचान पाने का सबसे तेज़ रास्ता विवाद है। मेहनत, अध्ययन और धैर्य कृ ये सब धीमे रास्ते हैं, जबकि दुनिया तुरंत नतीजे चाहती है। इस जल्दबाज़ी की कीमत युवा थकान, अकेलेपन और अंदरूनी खालीपन के रूप में चुका रहा है। अक्सर यह मान लिया जाता है कि प्लेटफ़ॉर्म तटस्थ हैं, लेकिन सच्चाई

यह है कि एल्गोरिद्म नैतिक नहीं होते। वे केवल लक्ष्य देखते हैं, और लक्ष्य है कृ अधिक समय, अधिक ध्यान। इसलिए वे वही दिखाते हैं जो हमें बाँधे रखे, चाहे वह नफ़रत हो, झूठ हो या खोखला मनोरंजन। ऐसे में ज़िम्मेदारी केवल प्लेटफ़ॉर्म की नहीं, हमारी भी है। हम जो देखते हैं, वही बढ़ता है। हम जिसे साझा करते हैं, वही फैलता है। इस सर्कस से बाहर निकलने का रास्ता कोई त्वरित समाधान नहीं है। यह एक धीमी लेकिन ज़रूरी क्रांति है। डिजिटल साक्षरता, गहरी सामग्री को सम्मान, ईमानदार रचनाकारों का समर्थन और अपने देखने–साझा करने के चुनावों के प्रति सजगता कृ यही वह रास्ता है जिससे दिशा बदली जा सकती है। असहमति को शालीनता के साथ जगह देना और तर्क को ट्रोलिंग पर तरजीह देना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। डिजिटल संसार का सर्कस बन जाना महज़ एक टिप्पणी नहीं, बल्कि चेतावनी है। सर्कस मनोरंजन देता है, दिशा नहीं। समाज को दिशा चाहिए कृ ज्ञान से, विवेक से और नैतिक साहस से। अंततः सवाल युवाओं से ही हैरू आप इस मेले का हिस्सा बनना चाहते हैं, या उस सन्नाटे के गवाह कृ और वाहक कृ जो सच के लिए ज़रूरी है? फैसला आज का है, असर आने वाले कल पर पड़ेगा। शोर आसान है, अर्थ गढ़ना कठिन। लेकिन इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है, जिन्होंने कठिन रास्ता चुना।

दौलत की फाइलें, भरोसे के सवाल

— डॉ. प्रियंका सौरभ

हरियाणा के आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति का विवरण सार्वजनिक होने के बाद एक बार फिर प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। जब जनता के सामने यह तथ्य आते हैं कि कानून–व्यवस्था संभालने वाले कई वरिष्ठ अधिकारियों के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति हैकृजमीन, प्लॉट, मकान, फार्महाउस या अन्य निवेशकृ तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में जिज्ञासा और सवाल दोनों पैदा होते हैं। यह सवाल केवल आंकड़ों का नहीं होता, बल्कि उस भरोसे का होता है जो जनता प्रशासन और शासन पर करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारी पद केवल अधिकार का प्रतीक नहीं होता, बल्कि वह जिम्मेदारी और नैतिक आचरण का भी प्रतीक होता है। विशेष रूप से पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी राज्य की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कानून लागू करते हैं, अपराध पर नियंत्रण रखते हैं और आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ऐसे में जब उनकी आर्थिक स्थिति चर्चा का विषय बनती है, तो जनता यह समझना चाहती है कि यह संपत्ति किस प्रकार अर्जित हुई, क्या यह पूरी तरह वैधानिक है, और क्या इस पर निगरानी की कोई प्रभावी व्यवस्था मौजूद है। संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करना निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। इससे शासन की पारदर्शिता बढ़ती है और नागरिकों को यह अधिकार मिलता है कि वे सत्ता से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत भी यही है कि सत्ता जनता से छिपी हुई नहीं होनी चाहिए। भारत में कई वर्षों से यह परंपरा रही है कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अपनी चल–अचल संपत्ति का विवरण सरकार को देते हैं। लेकिन जब यह जानकारी सार्वजनिक होती है, तब उसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि तब समाज स्वयं भी उस पर नजर रख सकता है। हालाँकि, केवल आंकड़े सामने आ जाने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। असली प्रश्न यह है कि क्या इन विवरणों की गंभीरता से जांच भी होती है? क्या यह सुनिश्चित किया जाता है कि घोषित संपत्ति वास्तविकता से मेल खाती है? क्या आय के स्रोत पूरी तरह स्पष्ट हैं? यदि यह प्रक्रिया केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाए तो पारदर्शिता का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। पारदर्शिता तभी सार्थक होती है जब उसके साथ जवाबदेही भी जुड़ी हो। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी सेवाओं में काम करने वाले सभी अधिकारियों को एक ही नजर से देखना उचित नहीं होगा। देश में अनेक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने ईमानदारी, सादगी और सेवा भावना की मिसाल कायम की है। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने कर्तव्य से समझौता नहीं किया। कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो वर्षों तक दूर–दराज के क्षेत्रों में काम करते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसी भी चर्चा को संतुलित दृष्टि से देखना आवश्यक है। कुछ मामलों के आधार पर पूरे तंत्र को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि पिछले

कुछ दशकों में प्रशासनिक तंत्र को लेकर जनता के मन में संदेह बढ़ा है। भ्रष्टाचार के कई मामलों ने लोगों का भरोसा कमजोर किया है। जब आम नागरिक रोजमर्रा के कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाता है, रिश्वत की शिकायतें सुनता है या व्यवस्था की जटिलताओं से जूझता है, तो उसके मन में यह भावना पैदा होती है कि कहीं न कहीं व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। ऐसे माहौल में जब बड़े पैमाने पर संपत्तियों की खबर सामने आती है, तो संदेह और गहरा हो जाता है।

यही कारण है कि संपत्ति के खुलासे को केवल समाचार की तरह देखने के बजाय इसे व्यवस्था को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए। सरकार और संबंधित संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संपत्ति घोषणाओं की नियमित और स्वतंत्र जांच हो। यदि कहीं कोई विसंगति पाई जाती है तो उस पर निष्पक्ष कार्रवाई भी हो। इससे ईमानदार अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और भ्रष्टाचार करने वालों के लिए स्पष्ट संदेश भी जाएगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रशासनिक तंत्र में नैतिक मूल्यों को मजबूत किया जाए। कानून और नियम जरूरी हैं, लेकिन केवल नियमों के सहारे पूरी व्यवस्था नहीं चलती। अधिकारियों के भीतर सेवा की भावना, जिम्मेदारी का एहसास और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा भी उतनी ही आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति उच्च पद पर पहुँचता है तो समाज उससे सामान्य नागरिक की तुलना में अधिक अपेक्षाएँ रखता है। यह अपेक्षा केवल कार्यकुशलता की नहीं बल्कि चरित्र और आचरण की भी होती है। मीडिया की भूमिका भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों का दायित्व है कि वे तथ्यों को सामने लाएँ, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करें। किसी भी खबर को सनसनी बनाने के बजाय उसके व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक संदर्भ को समझना भी जरूरी है। मीडिया यदि संतुलित और तथ्यपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाएगा तो समाज में स्वस्थ बहस का माहौल बनेगा। साथ ही नागरिक समाज की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र केवल सरकार या अधिकारियों से नहीं चलता; इसमें जनता की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी होती है। यदि नागरिक जागरूक होंगे, सवाल पूछेंगे और पारदर्शिता की मांग करेंगे तो व्यवस्था स्वाभाविक रूप से अधिक उत्तरदायी बनेगी। सूचना का अधिकार जैसे कानून इसी सोच का परिणाम हैं, जिन्होंने शासन को अधिक खुला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भी विचार करने योग्य है कि आज के समय में सरकारी सेवाओं में काम करने वाले अधिकारियों के सामने भी कई चुनौतियाँ हैं। लगातार बढ़ती अपेक्षाएँ, राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक जटिलताएँ और सामाजिक परिवर्तनकृइन सबके बीच काम करना आसान नहीं होता। इसलिए व्यवस्था को केवल आलोचना के दृष्टिकोण से देखने के बजाय सुधार के दृष्टिकोण से देखना अधिक उपयोगी होगा। यदि प्रशासन को मजबूत बनाना है तो उसे पारदर्शिता, प्रशिक्षण, तकनीकी सुधार और नैतिक नेतृत्वकृइन सभी पहलुओं पर एक साथ ध्यान देना होगा। डिजिटल युग में पारदर्शिता की संभावनाएँ और बढ़ गई हैं। यदि संपत्ति विवरण, प्रशासनिक निर्णय और वित्तीय प्रक्रियाएँ अधिक व्यवस्थित रूप से ऑनलाइन उपलब्ध हों तो भ्रष्टाचार की संभावनाएँ कम हो सकती हैं। कई देशों में यह व्यवस्था काफी प्रभावी साबित हुई है। भारत में भी इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि लोकतंत्र का आधार केवल कानून नहीं बल्कि विश्वास होता है। जनता का विश्वास ही सरकार और प्रशासन को वैधता देता है। यदि यह विश्वास कमजोर पड़ता है तो व्यवस्था की नींव भी कमजोर हो जाती है। इसलिए हर वह कदम जो पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करता है, वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करता है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति का मुद्दा भी इसी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह केवल कुछ नामों या आंकड़ों की कहानी नहीं है। यह उस रिश्ते का आईना है जो जनता और प्रशासन के बीच मौजूद है। यदि इस अवसर का उपयोग व्यवस्था को और पारदर्शी, जवाबदेह और नैतिक बनाने के लिए किया जाए, तो यह खबर केवल चर्चा का विषय नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव की शुरुआत भी बन सकती है। लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं होता; बल्कि वही व्यवस्था को जीवित रखता है। जरूरी यह है कि सवालों का जवाब भी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दिया जाए। तभी जनता का भरोसा मजबूत होगा।

अंतरराष्ट्रीय कॉक्लियर इम्प्लांट दिवस : आधुनिक चिकित्सा से सशक्तीकरण की ओर

—सुनील कुमार महला

प्रतिवर्ष 25 फरवरी को श्अंतरराष्ट्रीय कॉक्लियर इम्प्लांट दिवसश मनाया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट तकनीक के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन चिकित्सा इतिहास की एक गौरवशाली घटना का प्रतीक है। दरअसल, 25 फरवरी, 1957 को फ्रांसीसी चिकित्सक चार्ल्स आइरीज और आंद्रे जुरनो द्वारा दुनिया का पहला सफल कॉक्लियर इम्प्लांट किया गया था।

क्या है कॉक्लियर इम्प्लांट ?

पाठकों को बताता चलूं कि कॉक्लियर इम्प्लांट एक परिष्कृत छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसे सर्जरी के माध्यम से कान के आंतरिक हिस्से (कोक्लीया) में लगाया जाता है। यह उपकरण श्रवण तंत्रिका (आडिटरी नर्व) को सीधे उत्तेजित करता है, जिससे गंभीर रूप से सुनने में अक्षम व्यक्ति भी ध्वनियों को महसूस कर सकता है।

जागरूकता और मिथकों का निवारण–

वास्तव में, इस दिवस को मनाने का मुख्य लक्ष्य समाज में व्याप्त उन भ्रांतियों को तोड़ना है, कि जन्मजात मूक–बधिर बच्चे कभी सुन या बोल नहीं सकते। सच तो यह है कि यह दिन स्पष्ट संदेश देता है कि बहरेपन का उपचार संभव है। साथ ही, यह सरकारों और स्वास्थ्य संस्थाओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि आधुनिक तकनीक को हर जरूरतमंद के लिए सस्ती और सुलभ बनाया जाना अनिवार्य है।

श्रवण हानि–एक वैश्विक चुनौती–

वर्तमान में श्रवण अक्षमता एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती का रूप ले रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस संदर्भ में वर्तमान स्थिति की बात करें तो दुनिया भर में लगभग 43 करोड़ लोग (जिनमें 3.4 करोड़ बच्चे शामिल हैं) मध्यम से गंभीर श्रवण हानि से जूझ रहे हैं और यदि इस संबंध में समय पर निवारक उपाय नहीं किए गए, तो वर्ष 2050 तक यह संख्या 70 करोड़ से अधिक हो सकती है। यानी दुनिया का हर 10 में से 1 व्यक्ति इस समस्या से प्रभावित होगा। डब्ल्यूएचओ द्वारा श्विश्व श्रवण दिवसश (3 मार्च) से पूर्व जारी पहली वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, 2050 तक प्रत्येक 4 में से 1 व्यक्ति (लगभग 2.5 बिलियन लोग) किसी न किसी स्तर की श्रवण क्षति का सामना कर सकता है।भारत के संदर्भ में स्थिति की बात करें तो भारत में श्रवण संबंधी समस्याएं व्यापक हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 6 से 7 करोड़ लोग श्रवण अक्षमता से प्रभावित हैं। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष भारत में 27,000 से अधिक बच्चे जन्मजात बधिर पैदा होते हैं।

इस संदर्भ में व्याप्त विभिन्न चुनौतियां–

वास्तव में, श्रवण बाधा केवल सुनने की क्षमता तक सीमित समस्या नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक, शैक्षिक और भावनात्मक जीवन को प्रभावित करती है। श्रवण बाधित लोगों को संचार में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिससे शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार पाने और सामाजिक संबंध बनाए रखने में चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। आम जनता में जागरूकता की कमी, निदान में अनावश्यक देरी, कुपोषण, शोर प्रदूषण और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं इस समस्या को और जटिल बनाती हैं।

निवारण और सुधार के मार्ग–

श्रवण बाधा के निवारण और सुधार के लिए समय पर पहचान, उचित उपचार और जागरूकता बेहद आवश्यक हैं। गर्भावस्था में देखभाल, टीकाकरण, तेज आवाज़ से बचाव और कान के संक्रमण का इलाज रोकथाम में मदद करता है। जिन लोगों को समस्या है, उनके लिए हियरिंग एड, कॉक्लियर इम्प्लांट, स्पीच थेरेपी और सांकेतिक भाषा उपयोगी साधन हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सही हस्तक्षेप से कई मामलों में श्रवण हानि को रोका या कम किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में बड़ा सुधार किया जा सकता है और यह तभी संभव है जब हम नवजात शिशुओं की समय पर स्क्रीनिंग करवाएं।उनका नियमित टीकाकरण और सुरक्षित दवाओं का उपयोग किया जाए।अत्यधिक शोर से बचाव हो।श्रवण यंत्रों और इम्प्लांट तकनीक की व्यापक उपलब्धता से श्रवण बाधाओ का काफ़ी हद तक निवारण किया जा सकता है। अंत में निष्कर्ष के तौर पर यही कहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय कॉक्लियर इम्प्लांट दिवस हमें यह विश्वास दिलाता है कि आधुनिक विज्ञान ने सुनने की अक्षमता को अब एक श्बाधाश के बजाय श्उपचार योग्य स्थितिश बना दिया है। सहानुभूति से कहीं अधिक आवश्यक सशक्तीकरण है। सही समय पर पहचान और तकनीक का उपयोग न केवल सुनने की शक्ति लौटा सकता है, बल्कि प्रभावित व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा में भी स्थापित कर सकता है।

नये मतदाता फार्म- 6 भरते समय रखें विशेष सावधानियाँ

मोबाइल नम्बर दर्ज होने से आसानी से होगा ई-इपिक डाउनलोड
मतदाता फोटो पहचान पत्र त्रुटिरहित होने से मतदान के समय नहीं होगी असुविधा
पूर्व में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन हेतु भरें फार्म- 8

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा भरे जाने वाले फार्म–6 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया गया कि फार्म–6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरा जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि फार्म–6 में आवेदक का नाम व सही पता शुद्ध वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो एवं वर्तमान मोबाइल नम्बर अंकित किया जाना अति आवश्यक है, जिससे उन्हें निर्गत किये जाने वाले मतदाता फोटो पहचान पत्र त्रुटिरहित हो और भविष्य में मतदान के समय मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान करने में कोई असुविधा न हो।

1–फोटो संबंधी ध्यान रखने योग्य बातें

भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in तथा ECINET ऐप पर ऑनलाइन फार्म–6 भरने की सुविधा उपलब्ध है तथा फार्म–6 भरकर अपने बूथ लेवल अधिकारी को भी दिया जा सकता है। वर्तमान में जिन पात्र नागरिकों द्वारा मतदाता बनने हेतु फार्म–6 भरकर आवेदन किया जा रहा है उनमें से कई आवेदनों में यह पाया गया है कि आवेदक द्वारा लगायी गयी फोटो धुंधली, अस्पष्ट एवं आयोग के मानकों के अनुरूप नहीं है। मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान–पत्र में खराब गुणवत्ता वाली फोटो के कारण भविष्य में यदि मतदाता के पहचान की पुष्टि नहीं हो पाती है तो उसे मतदान के अधिकार से वंचित होना पड़ सकता है। अतः फार्म–6 में फोटो लगाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:–

मतदाता फोटो पहचान पत्र के लिए डिजिटल फोटोग्राफी के मानक–

आवेदक का डिजिटल फोटोग्राफ रंगीन, JPEG फार्मेट पर अधिकतम 2 डठ के आकार का होना चाहिए।

फोटो में आवेदक के सिर और कंधों के ऊपरी हिस्से का क्लोज–अप दिखना चाहिए।

फोटो की लम्बाई का 75 प्रतिशत हिस्सा चेहरे का होना चाहिए।

फोटो रंगीन, स्पष्ट फोकस एवं उच्च गुणवत्ता वाली पासपोर्ट साइज (4.5 सेमी/3.5 सेमी) की होनी चाहिए।

आवेदक की फोटो में कोई सिलवटें अथवा स्याही का निशान नहीं होना चाहिए।

मतदाता की फोटो कैमरे की ओर सीधे देखते हुए, भावहीन चेहरे, बंद मुँह एवं खुली आँखों के साथ होनी चाहिए। (भावहीन चेहरे का आशय सामान्य भाव है जिसमें चेहरे पर अधिक हँसी, क्रोध, शोक, आश्चर्य अथवा भय इत्यादि जैसे भाव नहीं होने चाहिए)

आवेदक की फोटो में उसके चेहरे के दोनों किनारे स्पष्ट दिखाई देने चाहिए।

फोटो में आवेदक की आँखें स्पष्ट रूप से दिखायी देनी चाहिए। आँखें बालों/टोपी/हेडकवर/घूँघट/छाया/प्रतिबिम्ब आदि से ढकी नहीं होनी चाहिए।

यदि आवेदक चश्मा पहनता है तो फोटो में आँखें स्पष्ट रूप से दिखायी देनी चाहिए और चश्मे में कोई प्रकाश प्रतिबिम्बित नहीं होना चाहिए। चश्मे के लेंस रंगीन नहीं होने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चश्मे का फ्रेम आवेदक के की आँखों के किसी भी हिस्से को न ढके। फोटो की पृष्ठभूमि सादी और हल्के रंग की होनी चाहिए और आवेदक के साथ कोई अन्य व्यक्ति व वस्तु दिखायी नहीं देनी चाहिए।

2–स्वयं एवं संबंधी का नाम भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें

आवेदक को स्वयं एवं अपने संबंधी का नाम हिंदी तथा अंग्रेज़ी, दोनों भाषाओं में साफ अक्षरों में सही–सही भरना चाहिए।

यदि केवल एक भाषा में नाम भरा जाता है तो, प्रणाली स्वतः दूसरी भाषा में रूपांतरण करेगी, जिससे नाम की वर्तनी में त्रुटि होने की संभावना हो सकती है।

संबंधी के नाम में आवेदक द्वारा अपने पिता/माता/पति/पत्नी में से किसी एक का तथा तृतीय लिंग के मामले में विधिक संरक्षक के रूप में गुरू का उल्लेख किया जायेगा।

विवाहित महिला आवेदकों द्वारा संबंधी के नाम में प्राथमिकता के आधार पर अपने पति का नाम भरना चाहिए।

आवेदन पत्र में जो विकल्प लागू न हो उसे काट दिया जाना चाहिए।

3–वर्तमान निवास का पता

फार्म–6 भरते समय आवेदक द्वारा अपने वर्तमान निवास का पूरा पता साफ–साफ शब्दों में लिखा जाना चाहिए। पता भरते समय निम्न प्रविष्टियाँ सही–सही भरी जानी चाहिए, जिससे कि मतदाता फोटो पहचान पत्र आवेदक को उसके पते पर आसानी से प्राप्त हो सके:–

मकान/भवन/अपार्टमेंट संख्या
गली/ क्षेत्र/स्थानीय क्षेत्र/मोहल्ला/सड़क
शहर/गाँव का नाम
डाकघर का नाम
पिनकोड
तहसील का नाम
जिले का नाम
राज्य का नाम

फार्म–6 में स्पष्ट पता अंकित करते समय अपने पते के नजदीक किसी लैण्डमार्क/महत्वपूर्ण स्थान को भी अंकित किया जाना चाहिए।

सामान्य निवास प्रमाण के लिए आवेदक को स्वयं/माता–पिता/पति–पत्नी के नाम पर निर्गत निम्नलिखित अभिलेखों में से किसी एक अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न करनी होगी:–

उस पते पर पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बिल (कम से कम एक वर्ष का)
आधार कार्ड
राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक/डाकघर की वर्तमान पासबुक
भारतीय पासपोर्ट
राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है
रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किरायेदार की दशा में)
रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में)

4–पिनकोड

प्रायः यह देखा गया है कि फार्म–6 में सामान्य निवास का पता भरते समय आवेदक द्वारा गलत पिनकोड भर दिया जाता है। त्रुटिपूर्ण पिनकोड के कारण मतदाताओं को उनका मतदाता फोटो पहचान पत्र उनके पते तक पहुँचने में महीनों का समय लग जाता है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि आवेदन करते समय सही पिनकोड अंकित किया जाये, जिससे मतदाता फोटो पहचान पत्र मतदाता को शीघ्र प्राप्त हो सके।

5–मोबाइल नंबर का महत्व

आवेदक द्वारा फार्म–6 में स्वयं का/पिता अथवा पति का मोबाइल नंबर अवश्य अंकित किया जाना चाहिए। मोबाइल नंबर अंकित करने से आवेदक द्वारा ओटीपी के माध्यम से अपने आवेदन को ईसीआई नेट ऐप (ECINET) या voters.eci.gov.in पोर्टल पर ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही पोर्टल/ऐप से ई–इपिक को एक से अधिक बार आसानी से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

अपील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि नये मतदाता बनने हेतु फार्म–6 भरते समय बताये गये उपर्युक्त बिन्दुओं का अवश्य ध्यान रखें। साथ ही अन्य मतदाता भी अपने मतदाता फोटो पहचान पत्र में लगी हुई फोटो तथा दिये गये पते एवं मोबाइल नंबर सहित अन्य प्रविष्टियाँ को पुनः जाँच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो अथवा संशोधन की आवश्यकता हो तो, फार्म–8 भरकर अपने बीएलओ को उपलब्ध करा दें अथवा ईसीआई नेट ऐप (ECINET) या voters.eci.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त क्षेत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न

होली के अवसर पर अतिरिक्त बसों का संचालन, सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करें - एम डी परिवहन निगम

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन. सिंह की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त क्षेत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। संचालन व्यवस्था, यात्रियों उन्होंने की सुविधा एवं सुरक्षा के साथ–साथ आगामी होली पर्व के अवसर पर विशेष परिवहन व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने होली के अवसर पर अतिरिक्त बसों का संचालन, सुचारु यातायात व्यवस्था, चालक परिचालकों की सतर्कता एवं यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। एम डी ने कहा कि सभी वाहनों की 13 एवं 31 बिंदुओं पर नियमित एवं अनिवार्य जाँच सुनिश्चित की जाए, जिससे बसों की तकनीकी स्थिति सुदृढ़ रहे और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, सभी चालकों एवं परिचालकों को प्रत्येक निर्धारित स्टॉप पर बस को अनिवार्य रूप से रोककर ,यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाए, जिससे यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित हो सके।

योगी सरकार का इंतजाम, होली पर 28 फरवरी से नौ मार्च तक चलेंगी अतिरिक्त बसें

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि, उत्कृष्ट कर्मचारियों को 3600 से 4500 रुपये तक प्रोत्साहन राशि
दिल्ली एवं गाजियाबाद सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसों और कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या पहले से सुनिश्चित की जाएगी

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। योगी सरकार ने होली पर्व पर यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। इसके तहत 28 फरवरी से नौ मार्च तक अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही, उत्कृष्ट कर्मचारियों को 3600 से 4500 रुपये तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

अनुबंधित बसों के कर्मियों को नहीं मिलेगा अवकाश

प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि दिल्ली एवं गाजियाबाद सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यात्रा का दबाव अधिक रहता है। इसलिए इन क्षेत्रों में बसों और कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या पहले से सुनिश्चित की जाएगी। यदि प्रारंभिक प्वाइंट से 60 प्रतिशत यात्री लोड मिलता है तो प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि शत–प्रतिशत निगम बसों को ऑनरोड रखा जाए और अनुबंधित बसों के कर्मियों को पर्व अवधि में अवकाश न दिया जाए। वाहन स्वामी समय से मरम्मत कार्य पूर्ण कर बसें संचालन हेतु उपलब्ध कराएं।

सुरक्षा और गुणवत्ता पर विशेष जोर

योगी सरकार ने यात्रा के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जाम या दुर्घटना की स्थिति को काबू कर संचालन सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवर्तन दल लगातार ड्यूटी पर रहेंगे तथा चालकों और परिचालकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाएगा। बसों की तकनीकी स्थिति दुरुस्त रहे, सीटें ठीक हों, खिड़कियों के शीशे सही हों और फायर सेफ्टी उपकरण उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बस स्टेशनों और बसों में स्वच्छता व्यवस्था भी सुदृढ़ रखने को कहा गया है।

कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना

पर्व अवधि में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चालक–परिचालकों (संविदा एवं आउटसोर्सिंग सहित) को विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रतिदिन औसतन 300 किमी संचालन करने पर 360 रुपये प्रतिदिन की दर से 3600 रुपये मिलेंगे । 10 दिन की पूर्ण ड्यूटी और निर्धारित मानक पूरा करने पर 450 रुपये प्रतिदिन की दर से 4500 रुपये और निर्धारित मानक से अधिक किलोमीटर पर प्रति किमी 55 पैसे अतिरिक्त मानदेय प्रदान किया जाएगा। डिपो एवं क्षेत्रीय कार्यशालाओं में कार्यरत कर्मचारियों को भी 10 दिन लगातार ड्यूटी पर 2100 रुपये तथा नौ दिन की ड्यूटी पर 1800 रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे।

उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अतिरिक्त सम्मान

प्रोत्साहन अवधि में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को क्षेत्रीय समिति की संस्तुति पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सर्वाधिक आय प्रति बस प्राप्त करने वाले तीन क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं सेवा प्रबंधकों तथा 10 डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

स्कॉर्पियो रुकवाकर रॉड, कुर्सी-टेबल से पीटा, घायल युवक आईसीयू में भर्ती

संवाददाता

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में शहीद पथ स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर देर रात दो पक्षों में बवाल हो गया। कुछ दबंगों ने हॉर्न बजाने पर स्कॉर्पियो पर तोड़फोड़ की। उस पर सवार युवक पर क्रेटा कार चढ़ा दी। सिर पर रॉड और कुर्सी–टेबल से पीट दिया। घायल पीड़ित युवक आईसीयू में भर्ती है। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आशियाना एलडीए कॉलोनी सेक्टर–ई निवासी पीड़ित नमन भटियानी ने बताया कि वह अपने दोस्त तुषार त्यागी (निवासी सनराइज ओमेक्स आर–1) के साथ रात करीब 2.30 बजे शहीद पथ स्थित कालिका रेस्टोरेंट पर खाना खाने गए थे। वहीं पर कुछ युवकों ने केवल हॉर्न बजाने पर उसे मारा–पीटा। आरोप है कि उनकी गाड़ी का हॉर्न बजाने पर वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों ने गाली–गलौज शुरू कर दी। जब गाली–गलौज का विरोध किया, तो आरोपियों ने कुर्सी–टेबल और अन्य सामान से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में तुषार त्यागी के सिर पर गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गए। नमन भटियानी ने आरोप लगाया कि उनके सिर पर लोहे के रॉड से वार किया गया था। आरोप है कि इसी दौरान एक व्यक्ति ने अपनी क्रेटा कार (यूपी 32 एसएम 3402) तुषार त्यागी के ऊपर चढ़ा दी। किसी तरह घायलों को कार में डालकर अस्पताल ले जाया गया। पहले उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर बाद में अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां तुषार इस समय आईसीयू में उपचार किया जा रहा है। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है।

संक्षिप्त

पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने गिनाई बजट और विभाग की उपलब्धियां

अब कोई छात्र स्कालरशिप से वंचित नही रहता : कश्यप
3402 करोड़ का भारी बजट मिला,आय सीमा में भी बढ़ोतरी

संवाददाता

लखनऊ। पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार ने नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट 3402 करोड़ रुपये किया गया है, जो पिछले वर्ष से लगभग 9 फीसदी ज्यादा है। अब कोई भी पात्र छात्र छात्रा स्कालरशिप से वंचित नही होता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का बजट 2140 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत 2023–24 से सभी पात्र छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल रही है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। छात्रवृत्ति वितरण अब 25 सितंबर से ही शुरू कर दिया गया है और अब तक लगभग 20 लाख छात्र–छात्राओं को समयपूर्व छात्रवृत्ति मिल चुकी है।उन्होंने बताया कि अभिभावकों की आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जा रही है, जिससे अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। पूर्वदशम छात्रों की छात्रवृत्ति 2250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये की गई है। 2026–27 में लगभग 38 लाख विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है।गरीब बेटियों के लिए शादी अनुदान योजना के तहत 2026–27 में 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आय सीमा को 1 लाख रुपये वार्षिक आय तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के 102 पिछड़ा वर्ग छात्रावासों के रखरखाव के लिए पहली बार 5 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। ट्रिपल सी एवं 'ओ' लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के लिए भी बजट रखा गया है।दिव्यांगजन पेंशन राशि 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। पेंशन मद में 1400 करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सभी 18 मंडलों में दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र डीआरसी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 7 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है।दिव्यांग छात्राओं के लिए 60 करोड़ रुपये की नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत उन्हें ई–ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। चित्रकूट स्थित दिव्यांग विश्वविद्यालय अब राज्य सरकार के अधीन आ गया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 500 करोड़ रुपये है।

एलयू में तीसरे दिन भी बवाल, नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ने गए छात्र हिरासत में

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय एलयू में आज लगातार तीसरे दिन भी बवाल जारी है। कैंपस में मुस्लिम छात्रों के नमाज पढ़ने के विरोध में आज दूसरे गुट के छात्र हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे थे। उनके इकट्ठा होते ही पुलिस भी पहुंच गई। छात्रों को पकड़–पकड़कर गाड़ी में ठूंस दिया। चालीसा पाठ करने गए छात्रों का कहना है कि जब यहां नमाज पढ़ी गई, इफ्तार पार्टी की गई तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हनुमान चालीसा पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? जिन्होंने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पर कुदाल चलाई, उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। हम जैसे उनका, उसी तरह अपने धर्म का भी सम्मान करते हैं। कई छात्रों के हिरासत में लिए जाने के बाद कुछ और छात्र लाल बारादरी बिल्डिंग पहुंचे। वहां बिल्डिंग पर गंगाजल छिड़का। बाद में बिल्डिंग के सामने राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल के छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लाल बारादरी बिल्डिंग है, जिसके अंदर मस्जिद होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, कई छात्रों का यह भी कहना है कि उसके अंदर एक छोटा मंदिर भी है। बिल्डिंग काफी जर्जर हो गई है, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन उसका रेनोवेशन करा रहा है। रविवार को जैसे ही खोदाई शुरू हुई, बड़ी संख्या में NSUI के स्टूडेंट मौके पर पहुंच गए। छात्रों ने निर्माण कार्य का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कहा– लाल बारादरी ैप द्वारा संरक्षित स्थल है, इसलिए बिना उसकी अनुमति के कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। रविवार को जिस जगह मुस्लिम छात्रों ने नमाज पढ़ी और इफ्तार किया, सोमवार को उसी जगह हिंदू छात्रों ने जय भवानी, जय श्रीराम के जयकारे लगाए। नमाज पढ़ने वाले छात्र उस स्थल पर निर्माण रुकवाने पहुंचे थे तो दूसरे गुट ने पहुंचकर नारेबाजी करते हुए उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।

लखनऊ में गूंजा 'बिजुरिया' फिल्म का नाम, भव्य अंदाज में हुआ टीजर लॉन्च

संवाददाता/ लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आज भारत की पहली एआई–लाइव एक्शन संयुक्त महिला सुपरहीरो फिल्म "बिजुरिया" का आधिकारिक टीजर लॉन्च भव्य रूप से संपन्न हुआ। यह फिल्म एक साधारण लड़की दिव्या की असाधारण यात्रा की कहानी है, जो आत्मविश्वास की कमी और सामाजिक भेदभाव से जूझते हुए अपनी पहचान तलाशती है। फिल्म उन महिलाओं की हकीकत को उजागर करती है, जो रोजाना उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करती हैं। कहानी में दिव्या की मुलाकात तेज नाम की एक बहादुर और वैज्ञानिक सोच रखने वाली युवती से होती है, जो उसकी जिंदगी बदल देती है। यह मुलाकात दिव्या को एक अनोखी सुपरहीरो में परिवर्तित कर देती है, जो समाज में व्याप्त कुरीतियों और अपराध के खिलाफ खड़ी होती है तथा महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती है। फिल्म के निर्देशक शारिब रजा ने बताया कि "बिजुरिया" महिला सशक्तिकरण को एक नए और आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि एआई तकनीक और लाइव–एक्शन के संयोजन से यह फिल्म भारतीय सिनेमा में एक नई दिशा स्थापित करेगी। फिल्म में मुख्य भूमिका लखनऊ की प्रतिभाशाली अभिनेत्री कंचन अवस्थी निभा रही हैं। थिएटर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली कंचन ने गन वाली दुल्हनिया, भूत वाली लव स्टोरी, चापेकर ब्रदर्स तथा टीवी सीरियल अम्मा में अपनी दमदार अदाकारी से पहचान बनाई है।

इलेक्ट्रीशियन ने फांसी लगाई, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक 27 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने उसे आनन–फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। नरही राधा कृष्ण मंदिर लेन निवासी सुमित कश्यप (27) प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन था। उसके पिता अशोक कश्यप ने बताया कि सुमित पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं जा रहा था। उसकी पत्नी कविता पिछले चार माह से अपनी तीन माह की बेटी के साथ चारबाग स्थित मायके में रह रही है। परिजनों के मुताबिक, सोमवार देर रात सुमित किसी काम से घर से बाहर गया था। कुछ देर बाद वह नशे की हालत में लौटा और सीधे अपने कमरे में चला गया। रात करीब 10.30 बजे जब पिता अशोक उसे खाना खाने के लिए बुलाने गए तो दरवाजा खोलने पर देखा कि वह पंखे के कुंडे में साड़ी के सहारे लटका हुआ है। यह देखते ही उनकी चीख निकल गई। आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंच गए। परिजन तुरंत उसे फंदे से उतारकर इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

लोहिया संस्थान में 24.86 करोड़ से बनेगा रैन बसेरा, राज्यपाल और डिप्टी सीएम ने किया भूमि पूजन

संवाददाता

लखनऊ। डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के शहीद पथ स्थित राम प्रकाश गुप्ता मेमोरियल मातृ एवं शिशु रेफरल चिकित्सालय में रोगियों और उनके परिजनों को ठहरने के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। रोगियों और परिजनों के लिए परिसर में रैन बसेरा भवन बनेगा। मंगलवार को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रैन बसेरा का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। साथ ही डायग्नोस्टिक सेवाओं का भी उदघाटन हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं। रोगियों को उनके घर के निकट इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए नए अस्पताल व मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के राम प्रकाश गुप्ता मेमोरियल मातृ एवं शिशु रेफरल चिकित्सालय में रोगियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में रोगियों को उच्च कोटि का इलाज मिल सके, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक रेफरल चिकित्सालय के रोगियों को सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्स–रे एवं अल्ट्रासाउंड जैसी आवश्यक जांचों के लिए अन्य परिसर अथवा दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता था। जिससे इलाज में विलम्ब होता था। डायग्नोस्टिक सुविधाओं को मातृ शिशु चिकित्सालय में बढ़ाया जाएगा ताकि एक ही स्थान पर रोगियों को इलाज के साथ जांच की सुविधा भी मिल सके। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि 24.86 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले पीआरए भवन का भूमि पूजन राज्यपाल ने किया। लगभग 510 बेड क्षमता वाले इस पीआरए–रैन बसेरा भवन का निर्माण होगा। इससे दूर–दराज से आने वाले रोगियों के परिजनों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं सम्मानजनक ठहराव की सुविधा प्राप्त होगी। इसमें कुल 45 कमरों में 90 बेड की व्यवस्था होगी। साथ ही डॉरमेटरी में 420 बेड की उपलब्धता होगी। रसोई, डायनिंग हॉल, लॉन्ड्री, 2 लिफ्ट, भोजन व्यवस्था, लिफ्ट तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का समुचित प्रावधान किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि शहीद पथ स्थित कैंपस में 1000 बेड के ब्रॉड स्पेशिलिटी सेवाओं का अस्पताल स्वीकृत हो गया है। यहां 100 शैय्या के क्रिटिकल केयर ब्लॉक हास्पिटल का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। साथ ही 888 कमरों का ब्वायज और गर्ल्स हॉस्टल का कार्य भी प्रगति में है। स्पोर्टस कॉप्लेक्स, नर्सिंग कॉलेज का काम चल रहा हैं। कार्यक्रम में राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, निदेशक, डॉ. राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान प्रो. सीएम सिंह, सीएमएस, मातृ एवं शिशु रेफरल सेंटर डॉ. श्रीकेश, सीएमएस डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान डॉ. विक्रम सिंह, डॉ. सुब्रत, डॉ. भुवन चंद्र, डॉ. प्रद्युमन सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

किसी भी बैंक का ऋण जमा अनुपात 40 फीसदी से कम न हो : डीएम

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में जिला बैंकर्स सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद में संचालित विभिन्न रोजगारपरक, स्वरोजगार एवं वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार एवं आंकड़ा आधारित समीक्षा की गई। ऋण–जमा अनुपात की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी बैंक का सीडी रेशियो 40 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक का सीडी रेशियो निर्धारित मानक से कम पाए जाने पर उन्होंने तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा में पाया गया कि कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा जनपद कन्नौज में लगभग 29,24.70 लाख की जमा राशि के सापेक्ष मात्र 51.83 लाख का ऋण वितरण किया गया है, जो अत्यंत कम है। जिलाधिकारी ने कहा कि इससे यह प्रतीत होता है कि जिले की जनता द्वारा जमा की गई धनराशि का समुचित लाभ स्थानीय स्तर पर नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने निर्देशित किया कि कन्नौज की जनता की जमा पूंजी का अधिकतम उपयोग जनपद में ऋण वितरण के माध्यम से किया जाए तथा सीडी रेशियो में प्रत्येक दशा में सुधार लाया जाए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपद को 1700 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 1248 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा 1215 लाभार्थियों को ऋण वितरण कर लाभान्वित

किया गया है। उन्होंने यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लक्ष्य के अनुरूप संतोषजनक प्रगति पर प्रशंसा व्यक्त की। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, एचडीएफसी बैंक एवं आईडीबीआई बैंक द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित प्रगति न किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं जनकल्याणकारी योजना है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि योजना की प्रतिदिन समीक्षा की जाए तथा जिन बैंकों द्वारा लक्ष्य पूर्ति में ढिलाई बरती जा रही है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, डूडा तथा अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बैठक से पूर्व योजनावार प्रगति, लंबित प्रकरणों की संख्या एवं आ रही समस्याओं का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करें, जिससे समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामकृपाल चौधरी, जिला विकास अधिकारी नरेंद्र देव द्विवेदी, उपायुक्त स्वतः रोजगार राजकुमार लोधी, अग्रणी जिला प्रबंधक डॉ. रंजीत सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच संवाद के लिए संवाद सेतु का आगाज

गाजियाबाद, हरदोई और कन्नौज से पायलट प्रॉजेक्ट की शुरुआत, अब 10 मिनट में सुनिश्चित होगा जवाब, कमांड सेंटर करेगा मॉनिटरिंग

बीएनई

कन्नौज। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच संवाद को अधिक सुगम, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में 25 फरवरी से 'संवाद सेतु' (जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर) व्यवस्था लागू की जाएगी। यह व्यवस्था पायलट प्रॉजेक्ट के रूप में गाजियाबाद, हरदोई और कन्नौज जनपदों में शुरू होगी। इस संबंध में समयबद्ध तैयारियों को लेकर समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने तीनों जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिससे योजना सुचारु रूप से लागू हो सके। फोन न उठने की समस्या का समाधान इस नई व्यवस्था के अंतर्गत हर जनपद में जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा।

अगर किसी अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधि की कॉल 10 मिनट के भीतर रिसीव या कॉल बैक नहीं की जाती है, तो जनप्रतिनिधि कमांड सेंटर को सूचित कर सकेंगे। कमांड सेंटर संबंधित अधिकारी को तुरंत कॉल बैक के लिए निर्देशित करेगा और संवाद सुनिश्चित करेगा। सम्मान भी, जिम्मेदारी भी यह व्यवस्था केवल कार्य दिवसों और कार्यालय समय में और सरकारी (सीयूजी) नंबरों पर लागू होगी। बेहतर संवाद और त्वरित प्रतिक्रिया देने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि लापरवाही की स्थिति में रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि यह पहल विधानसभा में उठे मुद्दे के बाद अमल में लाई जा रही है। इस संबंध में राज्यमंत्री असीम अरुण ने सुझाव दिया था।

आईओसी खिलाड़ी आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर बिंद्रा का कार्यकाल खत्म, केन्या के इस एथलीट ने ली जगह

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत के दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के खिलाड़ी आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर अपने आठ साल के कार्यकाल के खत्म होने की घोषणा की और अपने इस समय को अपनी खेल यात्रा के सबसे सार्थक अध्यायों में से एक बताया। बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने 43 साल के बिंद्रा की जगह पैनल में कीनिया के रग्बी खिलाड़ी हम्फ्री कायांगे ने ली। इटली मे शीतकालीन ओलंपिक के दौरान खिलाड़ी आयोग का पुनर्गठन किया गया। बिंद्रा ने एक्स पर किया पोस्ट बिंद्रा ने एक्स पर लिखा, दुनिया भर के खिलाड़ियों की सेवा करना खेल में मेरे सफर के सबसे सार्थक अध्याय में से एक रहा है। उनकी आवाज, उनकी चिंताओं, उनकी उम्मीदों और उनके सपनों को पूरा करना एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे मैंने कभी हल्के में नहीं लिया। हर बातचीत, हर फैसला, मेज पर हर पल एक ही सीधी सी सोच से चलता था कि खिलाड़ियों को हमेशा ओलंपिक अभियान के केंद्र में रहना चाहिए। अपने साथियों को असाधारण बताते हुए बिंद्रा ने कहा कि उनमें से हर

एक ने खिलाड़ी प्रतिनिधित्व को मजबूत करने और यह पक्का करने की कोशिश की कि उनकी आवाज सुनी जाए और उसका सम्मान किया जाए। बिंद्रा ने लिखा, मैंने जो बनाया है उस पर बहुत गर्व के साथ और आगे जो होने वाला है उसके लिए उम्मीद के साथ यह भूमिका छोड़ रहा हूं। खिलाड़ी प्रतिनिधित्व का भविष्य मजबूत है क्योंकि इसे हिम्मत वाले, सोचने वाले और जोशीले लोग चलाते हैं जो खुद से बड़ी किसी चीज में विश्वास करते हैं। 19 सदस्यों वाले आईओसी खिलाड़ी आयोग के सदस्य कई तरह की गतिविधियों का हिस्सा हैं जिसमें ओलंपिक के लिए उम्मीदवार शहर मूल्यांकन प्रक्रिया, खेलों के आयोजन का निरीक्षण, डोपिंग के खिलाफ लड़ाई और महिलाओं के लिए ट्रेनिंग तथा शैक्षिक परियोजनाओं का विकास करना शामिल है।

संक्षिप्त

क्या टाटा संस की कमान 2032 तक एन चंद्रशेखरन के हाथों में रहेगी ? तीसरे कार्यकाल पर फैसला

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित कारोबारी घरानों में से एक, टाटा समूह में शीर्ष नेतृत्व की निरंतरता बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। टाटा संस का निदेशक मंडल मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है, जिसमें समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के कार्यकाल को लगातार तीसरे पांच वर्षीय टर्म के लिए बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। 2032 तक कमान संभालने की तैयारी यदि टाटा संस का बोर्ड इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे देता है, तो चंद्रा के नाम से लोकप्रिय एन. चंद्रशेखरन वर्ष 2032 तक समूह के चेयरपर्सन के रूप में अपना पद सुरक्षित कर लेंगे। ध्यान रहे कि उनका मौजूदा दूसरा कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त होने वाला है। भारत के सबसे विविध और विशाल व्यापारिक समूह के शीर्ष पर इस विस्तार का उद्देश्य नेतृत्व में स्थिरता और एक स्पष्ट रणनीतिक निरंतरता प्रदान करना है। 1987 से लेकर टाटा संस के शिखर तक एन. चंद्रशेखरन का टाटा समूह के साथ एक लंबा और शानदार कॉर्पोरेट सफर रहा है। उन्होंने साल 1987 में कंपनी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद, उन्होंने साल 2009 से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया। 25 अक्टूबर 2016 को उन्हें टाटा संस के बोर्ड में नियुक्त किया गया था। बाद में, पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री को पद से हटाए जाने के बाद पैदा हुए विवादों के बीच, 2017 में चंद्रा को टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी की पूरी कमान सौंप दी गई थी।

उपमुख्यमंत्री व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने वैश्विक रक्षा कंपनियों से किया संवाद

जर्मनी में यूपी की दमदार दस्तक में रक्षा संबंधी निवेश को मिला समर्थन

लखनऊ ब्यूरो

जर्मनी/लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी मार्गदर्शन व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में जर्मनी पहुंचा प्रतिनिधिमंडल वहां के उद्यमियों से संवाद स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व प्रदेश सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को जर्मन–इजराइल की अग्रणी कंपनी क्वाटंम सिस्टम जीएमबीएच के साथ बैठक की। यह कंपनी मानवरहित और ड्रोन आधारित प्रौद्योगिकी की विशेषज्ञ है। यह कंपनी भारत में पिछले एक दशक से अधिक समय से उन्नत हवाई निगरानी तथा 160 किमी तक की परिचालन क्षमता वाले मानवरहित प्लेटफॉर्म में विशेषज्ञ है। इस कंपनी की टेक्नोलॉजी जर्मनी और स्पेन की सशस्त्र सेनाओं की सेवा में भी है। उपमुख्यमंत्री व आईटी मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारत की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र है। उप मुख्यमंत्री मौर्य व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री शर्मा ने क्वांटम टेक्नोलॉजीज को राज्य में ड्रोन मैन्युफेक्चरिंग, अनुसंधान एवं विकास (R-D) केंद्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया, जिससे यहां की प्रगतिशील नीतियां, मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और कुशल प्रतिभा–समूह का लाभ उत्तर प्रदेश को भी मिले। दोनों पक्षों ने मैन्युफेक्चरिंग, अनुसंधान– विकास, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में दीर्घकालिक सहयोग पर चर्चा की जिससे भारत के एयरोस्पेस और मानवरहित प्रणालियों के पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाया जा सके।

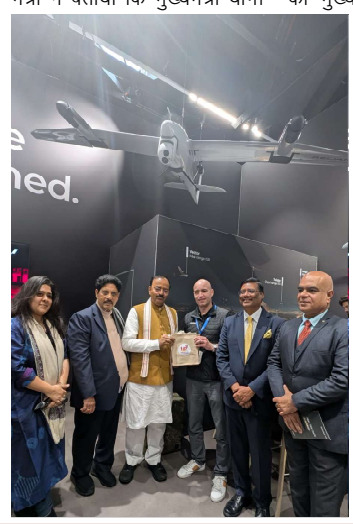

जल्द लौटाई जाएगी 7.11 लाख निष्क्रिय पीएफ खातों में पड़ी राशि, बंद होंगे 31.86 लाख खाते

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 7.11 लाख निष्क्रिय खातों में फंसे 30.52 करोड़ रुपये जल्द संबंधित खाताधारकों या उनके कानूनी वारिसों को लौटाए जाएंगे। श्रम मंत्रालय का यह फैसला ऐसे 31.86 लाख खातों को बंद करने की पहल का हिस्सा है, जो मौजूदा समय में निष्क्रिय पड़े हैं। मंत्रालय के मुताबिक इनमें कुछ खाते 20 साल तक पुराने हैं, जिनमें तीन साल से कोई लेनदेन नहीं हुआ। मंत्रालय ने बताया कि निष्क्रिय खातों को बंद करने के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी ऐसे सात लाख खातों को चुना गया है, जिनमें शून्य से 1,000 रुपये तक राशि जमा है और ये आधार से जुड़े हैं। लिहाजा, ईपीएफओ सीधे उनके खाते में यह पैसे ट्रांसफर कर देगा। इन खातों में 30.52 करोड़ रुपये जमा हैं। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर बाकी खातों में भी इसी तरह से पैसे लौटा दिए जाएंगे। निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भविष्य निधि एक अनिवार्य सरकारी योजना है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन का 12 फीसदी हिस्सा डालता है, जबकि नियोक्ता की ओर से भी उतना ही योगदान दिया जाता है। लेकिन, जब खाते में तीन साल तक कोई लेनदेन नहीं होता तो यह निष्क्रिय खाते में तब्दील हो जाता है। श्रम मंत्रालय अब ऐसे खातों को अब बंद करने की ओर बढ़ रहा है। कुल 10,903 करोड़ जमा ईपीएफओ में करीब 31.86 लाख निष्क्रिय पीएफ खाते हैं, जिनमें कुल 10,903 करोड़ रुपये जमा हैं। सरकार के मुताबिक ईपीएफओ सदस्य अपना पैसा निकालने के लिए अब आसानी से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन, यह भी देखने में आया है कि जिन खातों में पैसे कम हैं।

कैफ ने रणनीति पर उठाए सवाल, टीम चयन से लेकर बुमराह के इस्तेमाल और दुबे की गेंदबाजी तक पर साधा निशाना

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टी20 विश्व कप 2026 के सुपर–8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 76 रन की हार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका मानना है कि टीम इंडिया ने मुकाबला सातवें से 15वें ओवर के बीच गंवाया, जब डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस की साझेदारी ने मैच का रुख बदल दिया। इसके अलावा उन्होंने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी, जसप्रीत बुमराह के इस्तेमाल, छह बाएं हाथ के बल्लेबाजों को खिलाने और शिवम दुबे की गेंदबाजी पर भी निशाना साधा। बुमराह के इस्तेमाल पर सवाल कैफ ने खास तौर पर जसप्रीत बुमराह के इस्तेमाल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, श्हम मैच सात से 15 ओवर के बीच हार गए। आपने बुमराह के दो ओवर पहले करा दिए और बाकी दो डेथ के लिए बचाकर रखे। लेकिन रोहित

शर्मा ने कभी बुमराह का ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। कैफ ने आगे कहा, श्बुमराह मिडिल ओवर में एक ओवर डालकर साझेदारी तोड़ते थे। इस टीम में बुमराह से बड़ा मैच विनर कोई नहीं है। उन्हें पावरप्ले में एक ओवर और फिर 11वें या 12वें ओवर में लाना चाहिए था। रोहित की रणनीति का जिक्र कैफ ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की रणनीति का हवाला देते हुए कहा कि रोहित अक्सर पावरप्ले के बाद बुमराह को मिडिल ओवर में वापसी कराते थे, जिससे बड़ी साझेदारी टूटती थी। हालांकि इस मुकाबले में बुमराह ने पावरप्ले में क्विंटन डिकॉक और रेयान रिकेल्टन के अहम विकेट लिए, लेकिन बाद में उन्हें 17वें ओवर में वापस लाया गया, तब तक दक्षिण अफ्रीका 152/5 के मजबूत स्कोर पर पहुंच चुका था। दक्षिण अफ्रीका ने इस जीत के साथ भारत का 12 मैचों का अजेय क्रम तोड़ा और 76 रन से बड़ी जीत दर्ज की। शिवम दुबे पर भी निशाना कैफ ने शिवम दुबे के गेंदबाजी उपयोग पर भी सवाल खड़े किए। दुबे ने दो ओवर में 32 रन दिए। कैफ ने कहा, श्दुबे बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर नहीं। 10वें ओवर में कोई रक्षात्मक गेंदबाजी नहीं करता। उस समय आक्रमण करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, श्हमें 120 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाला ऑलराउंडर नहीं चाहिए। वह कभी–कभार विकेट ले सकता है, लेकिन रन भी खूब देगा। वेस्टइंडीज जैसी टीम के खिलाफ वह एक ओवर में चार छक्के भी खा सकता है। चयन और संतुलन पर सुझाव कैफ ने टीम संयोजन पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर को सलाह देते हुए कहा कि टीम में संतुलन जरूरी है। उनका कहना था, श्हम टॉप आठ में छह बाएं हाथ के बल्लेबाज खिला रहे हैं। अगर लेफ्ट–राइट कॉम्बिनेशन चाहिए तो उसी हिसाब से टीम चुनें। संजू सैमसन को मौका दीजिए। सेमीफाइनल की राह कठिन इस हार के बाद भारत का नेट रन रेट काफी गिर गया है और सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। अब टीम इंडिया को अपने बाकी दोनों सुपर–8 मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे ताकि नेट रन रेट सुधारा जा सके। रणनीतिक चूक और गेंदबाजी संयोजन पर उठे सवालों ने टीम प्रबंधन की चुनौती और बढ़ा दी है।

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने किया रकुल प्रीत सिंह को इग्नोर, वायरल वीडियो पर लोगों ने कहा- 'रकुल का अपमान किया'

एजेंसी

हाल ही में एक अवॉर्ड शो का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक फिटनेस इंफ्लुएंसर स्टेज पर ट्रॉफी लेने पहुंचे। वीडियो में दिख रहा है कि रकुल प्रीत सिंह ने उन्हें अवॉर्ड दिया और वो बिना हाथ मिलाए, बिना मुस्कुराए सीधे स्टेज से नीचे उतर गए। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने रकुल को इग्नोर कर दिया। क्या है पूरा मामला? फिटनेस इंफ्लुएंसर लक्ष्य जग्गी और रकुल का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें लक्ष्य बिना हाथ मिलाए बस अवॉर्ड लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लक्ष्य जग्गी ने खुद सामने आकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि लोगों ने उस मोमेंट को गलत समझ लिया। लक्ष्य के मुताबिक, उनसे पहले एक बुजुर्ग महिला को अवॉर्ड दिया गया था। उनका दावा है कि जब उस महिला ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो रकुल ने हाथ नहीं मिलाया। यह देखकर उन्हें लगा कि शायद उस समय स्टेज पर हाथ मिलाने की कोई परंपरा नहीं रखी गई है। लक्ष्य ने अपने वीडियो में कहा, 'मेरा किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था। मैंने अवॉर्ड लिया और आगे बढ़ गया क्योंकि मुझे लगा कि वहां हाथ मिलाने का रिवाज नहीं है। मुझे कैसे पता चलता कि सामने वाले को बुरा लग सकता है?' उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद किसी को नजरअंदाज करना नहीं था और पूरी घटना को गलत तरीके से पेश किया गया। कौन हैं लक्ष्य जग्गी? लक्ष्य जग्गी एक फिटनेस इंफ्लुएंसर हैं, जो सोशल मीडिया पर फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़े वीडियो बनाते हैं। उनके करीब 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

इस साल 9.1 फीसदी बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन, GCC में सर्वाधिक वृद्धि; रिपोर्ट में हुआ खुलासा

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय कंपनियां इस साल वेतन में औसतन 9.1 फीसदी की वृद्धि कर सकती हैं। हालांकि, यह 2025 के 9.3 फीसदी की अनुमानित वृद्धि से थोड़ा कम है। ईवाई ने सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा, कंपनियां कौशल आधारित वेतन ढांचे और बेहतर प्रदर्शन पर जोर दे रही हैं। कंपनियां वेतन वृद्धि के लिए इन मानकों को ही आधार बना रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) में सबसे ज्यादा 10.4 फीसदी वेतन वृद्धि की उम्मीद है। वित्तीय सेवा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन करीब 10 फीसदी बढ़ सकता है। ई–कॉमर्स में 9.9 फीसदी और लाइफसाइंसेज एवं फार्मास्यूटिकल्स में 9.7 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 45–50 फीसदी भारतीय कंपनियां कौशल आधारित वेतन ढांचे पर जोर दे रही हैं। एआई, जेनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग और इंजीनियरिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी भूमिकाओं में 40 फीसदी तक वेतन वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उच्च और औसत प्रदर्शन के बीच का अंतर बढ़ गया है। उच्च

प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के वेतन में करीब 120–150 फीसदी और औसत प्रदर्शन वाले कर्मियों के वेतन में 60–80 फीसदी की वृद्धि देखी जा रही है। 15 फीसदी तक बढ़ रहा सीईओ का वेतन रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में निफ्टी की शीर्ष–200 कंपनियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) का औसत कंपनसेशन (मुआवजा) बढ़कर 7–9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह सालाना आधार पर 12–15 फीसदी की बढ़ोतरी को दिखाता है। ईवाई के मुताबिक, इसमें से फिक्स्ड वेतन कुल सीईओ कंपनसेशन का 25–30 फीसदी है। शॉर्ट–टर्म इंसेंटिव (प्रोत्साहन) की हिस्सेदारी 25–30 फीसदी है, जबकि लॉन्ग–टर्म प्रोत्साहन का 45–50 फीसदी योगदान है। एनएसई–200 कंपनियों में से करीब 75 फीसदी लॉन्ग–टर्न प्रोत्साहन देती हैं, जो सीईओ के कंपनसेशन का एक मानक हिस्सा बन जाता है। नौकरी छोड़ने की दर में गिरावट रिपोर्ट के मुताबिक, नौकरी छोड़ने की दर (एट्रिशन रेट) 2025 में घटकर 16.4 फीसदी रह गई, जो एक साल पहले 17.5 फीसदी रही थी। यह गिरावट श्रम बाजार में सुस्ती के चलते आई है, जहां कर्मचारियों की जोखिम लेने की क्षमता कम हो गई है। 80 फीसदी ज्यादा कर्मचारी मर्जी से नौकरी छोड़ रहे हैं। ज्यादातर एट्रिशन कर्मचारी और अवसर आधारित हैं, न कि पुनर्गठन की वजह से। वित्तीय सेवा क्षेत्र में नौकरी छोड़ने की दर सबसे ज्यादा 24 फीसदी रही। खासकर सेल्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और डिजिटल भूमिकाओं में। पेशेवरों सेवाओं में एट्रिशन रेट 21.3 फीसदी रही, जबकि हाई–टेक और आईटी क्षेत्र में नौकरी छोड़ने की दर 20.5 फीसदी रही। वैश्विक क्षमता केंद्रों यानी जीसीसी में एट्रिशन रेट सबसे कम 14.1 फीसदी रही। वेतन का भविष्य सिर्फ सालाना इंक्रीमेंट पर निर्भर नहीं ईवाई इंडिया के पार्टनर एवं लीडर अभिषेक सेन ने कहा, भारत में वेतन का भविष्य अब सिर्फ सालाना इंक्रीमेंट के साइज से तय नहीं होता। कंपनियां अब तय कर रही हैं कि किस कौशल में निवेश करना है और किन नतीजों को प्रोत्साहित करना है। रिवॉर्ड रणनीति ज्यादा सोच–समझकर बनाई जा रही हैं, जिसमें फैसले लेने के लिए डाटा का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743